

‘मैं कांग्रेस का राज्यसभा का उम्मीदवार हूँ, कल पर्चा भर रहा हूँ, आप आ जाएं’

करमवीर बौद ने यह फोन भूपेन्द्र हूडा, सुरजेवाला, शैलजा आदि को किया, सभी नेता स्तब्ध रह गये

कोटा का डॉक्टर बना यूपीएससी टॉपर

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 6 मार्च। राजस्थान के लिए गर्व का पल। कोटा के अनिल अग्रिहोत्री, जो पेशे से डॉक्टर हैं, ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेस एग्जामिनेशन (सीएसई) 2025 में टॉप रैंक हासिल की है। यह उपलब्धि उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में हासिल की।
अनुज अग्रिहोत्री ने इस परीक्षा में टॉप किया, जबकि राजेश्वरी सुवे एम

■ डॉ. अनुज अग्रिहोत्री ने तीसरे प्रयास में यह शानदार सफलता प्राप्त की है। उन्होंने मैडिकल साइन्स को बतौर विषय चुना था।

और आकाश धुल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। अनुज ने मेडिकल साइंस को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुना था।

अपनी इस अद्वितीय उपलब्धि के बाद एनडीटीवी से बात करते हुए, 26 वर्षीय अनुज ने कहा, “मैं अपनी सफलता का मुख्य कारण भाग्य को मानता हूँ।”

अनुज को टॉप करने की यात्रा आसान नहीं थी। यह उनका तीसरा प्रयास था। पहले प्रयास में उन्हें दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

क्या ट्रम्प ईरान युद्ध के तनाव से टूट से रहे हैं?

वे वाइट हाउस में अपनी “ऑफिशियल” कुर्सी में सम्मोहित से बैठे नज़र आए, अपनी पूजा में आंख बंद किए अपने प्रभु से मदद मांगते हुए

—अंजन रॉय—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 6 मार्च। सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ईरान युद्ध के दबाव में झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं।

कोई हैरानी नहीं कि ईरान ने, उनके वेंनेजुएला अनुभव की तुलना में, जिस तरह जबरदस्त जवाबी हमला किया है और ईरान युद्ध में मदद देने को लेकर उनके नाटो सहयोगियों के बीच साफ मतभेद भी सामने आ गए हैं, ऐसी स्थिति में ट्रंप को अपने मौजूदा संकट से निकलने के लिए हर तरह की भौतिक, आध्यात्मिक और यहां तक कि अलौकिक मदद की ज़रूरत महसूस हो रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास, द वाइट हाउस, आज असाधारण दृश्यों का गवाह बना। एक बड़े व्यक्तिको तरह ट्रंप आत्माओं की दुनिया से तुरंत मदद की प्रार्थना करते हुए एकदम स्तब्ध बैठे थे।

यह एक अजीब सा नाटक जैसा दृश्य था, जब अमेरिका के राष्ट्रपति को धार्मिक नेताओं द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा था, वह भी ओवल ऑफिस जैसे

■ यह सच है कि, जिस “आराम” से वे वेंनेजुएला पर विजय पा सके थे, उसकी तुलना में ईरान के आक्रामक जवाब ने उन्हें हिला दिया है। ट्रंप के आसपास विभिन्न धर्मों के धार्मिक गुरु, उनके सिर पर, कंधे पर हाथ लगाकर हिम्मत बढ़ाते नज़र आये। वे ऐसे हारे हुए व्यक्ति लग रहे थे मानो उन्हें दूसरी दुनिया से मदद की ज़रूरत महसूस हो रही थी।

■ वैसे भी ट्रंप अब विरोधाभासी दावे कर रहे हैं, जिनका तथ्यों से कोई सरोकार नहीं लगता।

■ एक तरफ तो वे, ईरानी दूतावासों के अधिकारियों से कह रहे हैं, कि वे अपनी जिम्मेवारी छोड़कर बाहर आ जायें, और अन्य देशों की सरकारों से संरक्षण की मांग करें। दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का ट्रैफिक खुलवाने की कोशिश में, व्यवसायिक जहाजों को अमेरिकी नौ सेना की सुरक्षा में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करवाने का वादा करते हैं।

स्थान पर। ट्रंप अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठे थे और उनके चारों ओर कई धार्मिक नेता खड़े होकर गंभीर स्वर में शांति, सबके लिए न्याय और इसी तरह की बातें कर रहे थे।
इन धार्मिक नेताओं को अमेरिकी

राष्ट्रपति को झूठे हुए देखा गया, कुछ उनके हाथ पकड़ रहे थे, तो कुछ उनके कंधों पर हाथ रखे हुए थे। ट्रंप आंखें बंद किए, परेशान चेहरे के साथ अपनी कुर्सी पर असहज तरीके से बैठे दिखाई दे रहे (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार में एक अनजाने चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है भाजपा

चर्चा है कि संघ पृष्ठभूमि वाली सीमा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है

—श्रीनंद झा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 6 मार्च। ऐसी संभावनाएँ हैं कि भाजपा नेतृत्व बिहार में नीतीश कुमार के स्थान पर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसी कम पहचान वाली महिला नेता को नियुक्त कर सकता है, जैसा कि भजनलाल शर्मा के मामले में किया था।

अंतरराष्ट्रीय घटनाओं, जैसे इजराइल-ईरान युद्ध और एस्टॉन फाइलिंग में भाजपा और केन्द्र सरकार व्यस्तता के बीच, अंततः नीतीश कुमार को दरबाजा दिखा देने का निर्णय एक आश्चर्यचकित करने वाला कदम साबित हुआ है। लेकिन दो पुरे महत्वपूर्ण हैं। पहला, भाजपा शांति ट्रीटमेंट देने की अपनी क्षमता पर फलती-फूलती आ रही है। दूसरा, बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होना पार्टी के लिए पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के चुनावों में मददगार साबित होगा। इससे भी ज्यादा

■ इस कदम से भाजपा को कई लाभ होने की संभावना है। एक तो वह बिहार में नई शुरुआत का संकेत देना चाहती है। दूसरे पार्टी को उम्मीद है कि इससे पड़ोसी राज्य प.बंगाल, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, में भारी फायदा होगा।

■ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के असंभव कार्य में सफल होने के बाद भी भाजपा कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा पर उपमुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के पुत्र से पेशकश की गई है।

■ सुत्रों ने कहा, भाजपा जद (यू) में विभाजन की कोशिश भी नहीं करेगी क्योंकि नीतीश कुमार के प्रति भारी सहानुभूति है लोगों, खासकर महिलाओं में, इसलिए भाजपा कोई दुस्साहस नहीं करेगी और नीतीश के प्रति भारी सद्भावना दिखाएगी।

फायदा उस स्थिति में होगा, अगर कम पहचान वाली महिला नेता का भाजपा नेतृत्व इस काम के लिए किसी (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

उमेश सिंह कुशवाहा जदयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने

पटना, 06 मार्च। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ नेता उमेश सिंह कुशवाहा को लगातार तीसरी बार पार्टी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। शुरुआत को पटना स्थित जदयू के प्रदेश कार्यालय में संगठनात्मक चुनाव की निर्धारित

■ वे लगातार तीसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया गया।

प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी अशोक कुमार ‘मुन्ना’ और परमहंस कुमार ने उन्हें अध्यक्ष पद का प्रमाण-पत्र सौंपा। इससे पहले उमेश सिंह कुशवाहा ने चार सैट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। तय समय-सीमा तक इस पद के लिए उनके अलावा किसी अन्य नेता ने नामांकन नहीं किया। इसके बाद स्कूटनी प्रक्रिया पूरी होने पर उन्हें निर्विरोध बिहार प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया।

‘अमेरिका ने दया की, भारत को रुस से कच्चा तेल लेने की अनुमति दी’

अमेरिका के ट्रैजरी सैक्रेटरी ने कहा कि भारत को यह काम चलाऊ छूट सिर्फ 30 दिनों के लिए दी गई है।

—डॉ. सतीश मिश्रा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 06 मार्च। दया भाव

दर्शाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भारत को “अस्थायी” रूप से रुस से कच्चा तेल खरीदने की अनुमति दे दी है, और इस पर कोई दंडात्मक शुल्क नहीं लिया जाएगा और भारतीय सरकार ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करते हुए रिफाइनरियों को रसोई गैस की कमी से बचने के लिए एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया, क्योंकि मध्य पूर्व युद्ध के कारण एलपीजी की भारी कमी हो सकती थी।

कतर से, जो भारत का प्रमुख एलपीजी आपूर्तिकर्ता है, चिंताजनक रिपोर्ट मिलने के बाद मोदी सरकार ने अमेरिकी राहत का तुरंत उपयोग किया, ताकि घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति में आने वाले संकट को टाला जा सके।
“द फाइनेंशियल टाइम्स” से एक

■ स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत इस अवधि में रुस से वही तेल खरीद पाएगा जो पहले से समुद्र में विचरण कर रहे टैंकरों में जमा है और इससे रुस को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इससे ईरान युद्ध से बड़े दबाव से भारत को कुछ राहत मिलेगी। तथापि, भारत को इसके लिए मौजूदा रेट पर ही कीमत अदा करनी होगी।

■ इस अनुमति के साथ ही भारत ने तेल मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। दो टैंकर भारत की ओर निकल चुके हैं इनमें से हरेक में 7 लाख बैरल तेल है, चर्चा है कि तीसरा टैंकर भी भारत की ओर बढ़ रहा है।

■ इस समय रुस का 9.5 लाख मिलियन बैरल कच्चा तेल समुद्री टैंकरों में जमा है और भारत के आसपास ही मंडरा रहा है।

■ भारत सरकार ने भारतीय तेल कंपनियों को रसोई गैस का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं।

साक्षात्कार में, कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल काबी ने कहा कि युद्ध के कारण खाड़ी देशों में ऊर्जा उत्पादन बंद हो सकता है, तेल की कीमत 150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है और “दुनिया

की अर्थव्यवस्थाओं को नीचे ला सकता है”।
कतर, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिक्विड नैचुरल गैस (एलएनजी) उत्पादक है, इस सप्ताह अपने रास

लाफन संयंत्र पर एक ईरानी ड्रोन हमले के बाद उत्पादन रोकने पर मजबूर हो गया, जो कि इसका सबसे बड़ा एल पी जी संयंत्र है।
(श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है नाटो देशों में

नाटो के सदस्य देश अमेरिका से अलग, स्वतंत्र विदेश नीति पर चलने के संकेत दे रहे हैं

—सुकुमार साह—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 6 मार्च। ईरान के

खिलाफ युद्ध में अमेरिका का साथ देने से स्पेन के इनकार ने हाल के वर्षों में पश्चिमी गठबंधन के भीतर सबसे गंभीर मतभेदों में से एक को उजागर कर दिया है। हालांकि स्पेन नार्थ एटलान्टिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (नाटो) का सदस्य है, लेकिन प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ की सरकार ने साफ कर दिया है कि मैड्रिड न तो इस सैन्य अभियान में भाग लेगा और न ही स्पेन की जमीन को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करने देगा। इस रुख ने स्पेन को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ सीधे टकराव में ला दिया है और इससे ट्रांस-अटलान्टिक गठबंधन की एकता पर भी बड़े सवाल उठे हैं।

■ स्पेन द्वारा अमेरिका को ईरान के खिलाफ सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देना इसी की शुरुआत माना जा रहा है।

■ स्पेन का कहना है कि नाटो का सदस्य होने का मतलब अमेरिका के हरेक सैन्य अभियान में अनिवार्य रूप से भागीदारी करना नहीं है।

■ स्पेन व अन्य देशों में अमेरिका के प्रति बढ़ते असंतोष की एक बड़ी वजह उन देशों की आंतरिक राजनीति भी है। स्पेन में जनभावना दूसरे देशों, खासकर मिडिल ईस्ट, में सैन्य हस्तक्षेप के सख्त खिलाफ है। स्पेन का मत है कि युद्ध लंबा खिंचा तो, मिडिल ईस्ट अस्थिर हो जाएगा और इससे यूरोप पर शरणार्थियों का भार पड़ेगा।

■ स्पेन का यह रुख इराक वॉर की कटु स्मृतियों के कारण है। वर्ष 2003 में स्पेन की तत्कालीन सरकार ने इराक में अमेरिकन घुसपैठ का समर्थन किया था, इस पर स्पेन में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था, लोग सड़कों पर उतर आए थे। मैड्रिड में ट्रेन धमाके हुए, जिसमें 200 लोग मारे गए थे। बाद में जब वहां समाजवादी सरकार बनी तो उसने इराक से अपने सैनिक वापस बुला लिए थे।

विवाद की तात्कालिक वजह यह है कि स्पेन ने अमेरिका को अपने संयुक्त सैन्य टिकानों, नेवल स्टेशन रोटा और

मोरोन में अपने जॉइंट मिलिट्री बेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ युद्ध से जुड़ी कार्रवाई के लिए करने की अनुमति देने

से इनकार कर दिया। इन टिकानों पर, लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय रक्षा समझौते के तहत, अमेरिकी सेना मौजूद

रहती है और ये भूमध्यसागर तथा मध्य-पूर्व में अमेरिकी अभियानों के लिए महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक केन्द्र रहे हैं।

मैड्रिड ने जोर देकर कहा है कि इन टिकानों का इस्तेमाल ऐसे आक्रामक सैन्य अभियानों के लिए नहीं किया जा सकता, जिनके लिए अंतरराष्ट्रीय कानून या संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क के तहत कोई साफ मैनडेट न हो। इस तरह रेखा खींचकर सांचेज़ सरकार ने वॉशिंगटन को स्पेन की जमीन को इस संघर्ष के लिए लॉजिस्टिक पैड के रूप में इस्तेमाल करने से रोक दिया।

यह विवाद जल्दी ही मैड्रिड और वॉशिंगटन के बीच एक डिप्लोमैटिक टकराव में बदल गया। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से स्पेन की आलोचना करते हुए कहा कि उसने गठबंधन को एकजुटता का साथ नहीं दिया और यहां तक कि ट्रेड में बदले की कार्रवाई का संकेत भी दिया। हालांकि स्पेन अपने फैसले पर (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा के सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी

नई दिल्ली, 06 मार्च। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुरुआत को सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्वल भविष्य की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में कहा,

■ उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को उनकी समर्पण भावना, दृढ़ता व कड़ी मेहनत ने इस उपलब्धि तक पहुंचाया है।

सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को बधाई। उनकी समर्पण भावना, दृढ़ता और कड़ी मेहनत ने उन्हें इस महत्वपूर्ण उपलब्धि तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री ने एक अन्य पोस्ट में उन अभ्यर्थियों का भी हौसला (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

किसी को अपना व्यक्तित्व छोड़कर दूसरे का व्यक्तित्व नहीं अपनाना चाहिए। -चैनिंग

राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण

राजस्थान, रेगिस्तान की भूमि, जहां बालू के टीले इतिहास की गाथाएं गुनगुनाते हैं और किले-महल सूरज की किरणों में चमकते हैं, आज एक अनोखे वैभव के दौर से गुजर रहा है। यह वैभव आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चकाचौंध और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शहनाहा का मेल है। एक ओर जहां हाई-स्पीड रेलमार्ग, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं और डिजिटल हाइवे राजस्थान को भविष्य की ओर ले जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोक कला, परंपरिक हस्तशिल्प और आध्यात्मिक विरासत नई ऊर्जा के साथ पुनरुत्थान कर रही है। यह नया अध्याय न केवल आर्थिक विकास का प्रतीक है, बल्कि राजस्थान की आत्मा को संरक्षित करते हुए उसे वैश्विक पटल पर चमकाने का माध्यम भी बन रहा है।

कल्पना कीजिए, जयपुर के हवा में लहरते नौसे गुजराती मेट्रो ट्रेने, जो राजपूताना की भव्यता को आधुनिक गति प्रदान कर रही है। या फिर उदयपुर के झीलों के किनारे विकसित हो रही स्मार्ट टूरिज्म सुविधाएं, जहां ड्रोन तकनीक से संचालित लाइट शो फुटेज सिंघे के काल की कहानियां जीवंत कर देते हैं। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्क्रीम और स्मार्ट सिटी मिशन ने राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर का हब बना दिया है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर जैसे शहरों में मेट्रो रेल, एयरपोर्ट विस्तार और हाईवे नेटवर्क का जाल बिछ चुका है। उदाहरणस्वरूप, दिल्ली-जयपुर हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, जो 2026 तक चालू होने की कगार पर है, यात्रा के समय को आधा कर देगा। इससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय कारीगरों के उत्पाद वैश्विक बाजार तक पहुंच सकेंगे।

यह इंफ्रास्ट्रक्चर केवल कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं है; यह सांस्कृतिक पुल है। राजस्थान के गांवों में सोलर पैनल खेतों के बीच अपनी अलग छटा बिखेर रहे हैं। राज्य सरकार को राजस्थान क्राफ्ट प्रमोशन नीति ने हस्तशिल्प को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। ई-कॉमर्स साइट्स जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर बगर प्रिंट, कठपुतली और बंधेज साड़ियां विक्रि रही हैं, जो सीधे कारीगरों के हाथों से ग्राहक तक पहुंचती हैं। जयपुर का ब्लू पॉटरी अब 3डी प्रिंटिंग तकनीक से संयोजित होकर आधुनिक डिजाइन में उपलब्ध है। यह पुनर्जागरण सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है, जहां परंपरा और तकनीक का संगम हो रहा है।

जोधपुर, ब्ल्यू सिटी, जहां थार एक्सप्रेसवे ने रेगिस्तान को पार करने का समय घटाकर दो घंटे कर दिया है, अब सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। यहां के उम्रद भवन पैलेस को होटल ताज ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है, लेकिन साथ ही स्थानीय लोक संगीत को प्रमोट करने के लिए रूज फेस्टिवल आयोजित हो रहे हैं। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने पर्यटन को बढ़ावा दिया है, जो 2025 में 10 करोड़ पर्यटकों का आंकड़ा पार कर चुका। इससे उत्पन्न राजस्व सांस्कृतिक संरक्षण में लगाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, बीकानेर के जूनागढ़ किले में वरुचुल रियल्टी (वीआर) टूर शुरू हुआ है, जो पर्यटकों को राठीज राजाओं के युग में ले जाता है। यह तकनीक न केवल शिक्षा प्रदान करती है, बल्कि राजस्थानी इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाती है।

उदयपुर, झीलों का शहर, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित हो रहा है। यहां के पुष्कर झील पर प्लॉटिंग सोलर प्लांट न केवल ऊर्जा प्रदान कर रहा है, बल्कि सांस्कृतिक उत्सवों को रोशन कर रहा है। राजस्थान दिवस समारोह में ड्रोन शो के माध्यम से मेवाडा की वीर गाथाएं दिखाई जाती हैं। यह मेल आधुनिकता और परंपरा का प्रतीक है। इसी तरह, अलवर में भृगुहरि मंदिर के आसपास विकसित हो रही ग्रीन हाइवे परंपरागत लोक नृत्यों को स्टेज दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर ने रोजगार सृजन किया है - निर्माण क्षेत्र में 5 लाख नौकरियां पैदा हुईं, जो स्थानीय कलाकारों को सशक्त बना रही हैं। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह अब डिजाइन ब्लॉक प्रिंटिंग यूनिट चला रहे हैं, जो एयरपोर्ट पर स्टोर के माध्यम से विक्रित हैं।

लेकिन यह पुनर्जागरण केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं। ग्रामीण राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिछे सड़क नेटवर्क ने दूरदराज के गांवों को मुख्यधारा से जोड़ा है। बाइमेर के रेगिस्तानी गांवों में सोलर-पावर्ड कम्युनिटी सेंटर्स लोक कथाओं और कठपुतली शो के लिए केंद्र बन गए हैं। यहां के मांगणिया संगीतकार अब यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर अपनी रचनाएं अपलोड कर रहे हैं, जो सरहद्दी संस्कृति को वैश्विक बनाती हैं। राज्य की कलाकृति योजना ने 50 हजार कारीगरों को प्रशिक्षण दिया, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग शामिल है। इससे उनकी आय दोगुनी हो गई। यह सांस्कृतिक पुनरुत्थान आर्थिक सशक्तिकरण का आधार बन रहा है।

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने सांस्कृतिक पर्यटन को नया आयाम दिया। जयपुर का चौबीस ढाणी अब इको-रिसॉर्ट के रूप में विकसित हो गया, जहां सोलर एनर्जी से चलने वाले पारंपरिक ढाबे लोक भोजन परोसते हैं। दुनिया भर से पर्यटक आकर घूमर नृत्य और कालबेलिया संगीत का आनंद लेते हैं, जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में है। कोटा में चंबल नदी पर बने ब्रिज ने बारादीरी उत्सव को नया रूप दिया। यह सब राजस्थान को कल्चरल हब ऑफ इंडिया बनाने की दिशा में कदम है।

चुनौतियां भी हैं। तेज विकास में पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। थार रेगिस्तान में हाईवे निर्माण से जैव विविधता प्रभावित हो रही है। लेकिन राज्य सरकार ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। आईआईटी जोधपुर और बीआईटीएस पिलानी जैसे संस्थान अब राजस्थानी कला पर शोध कर रहे हैं। स्टार्टअप जैसे राज दीर्घा पारंपरिक ज्वेलरी को मॉडर्न डिजाइन से जोड़ रहे हैं।

राजस्थान में मंदिरों के प्रति भाव एवं रुझान हमारी पुरातन संस्कृति की तरफ एक कदम है। कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के अलावा अब छोटे-छोटे प्राकृतिक सुरम्य वातावरण में स्थित शिव मंदिर भी अपनी अलग छटा बिखेर रहे हैं।

यह नया अध्याय राजस्थान की आत्मा को मजबूत कर रहा है। जहां एक ओर बुलेट ट्रेन रेल के टीलों को पार करेगी, वहीं लोककला नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षक बनेगा। राजस्थान अब न केवल इतिहास का भंडार है, बल्कि भविष्य का प्रतीक भी। यह पुनर्जागरण हमें सिखाता है कि परंपरा और प्रगति का संतुलन ही सच्ची प्रगति है। आने वाले दशक में राजस्थान विश्व पटल पर चमकेगा, अपनी नीली छत्रियों, सुनहरी रेत और आधुनिक आकाशचुंबी इमारतों के साथ। यह अध्याय अभी शुरू हुआ है, और इसका अंतिम पृष्ठ हम सब मिलकर लिखेंगे।

-अतिथि संपादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार



अलका सक्सेना

समानता का अर्थ केवल अवसर देना नहीं, बल्कि ऐसा समाज बनाना है जहाँ अवसर, सम्मान और जिम्मेदारियाँ स्वाभाविक रूप से साझा हों।

लैंगिक समानता आधुनिक समाज के सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किए गए आदर्शों में से एक है। संविधान, नीतियों और सार्वजनिक विमर्श में इसका स्पष्ट समर्थन दिखाई देता है। फिर भी जब हम जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को देखते हैं, तो यह वादा अक्सर अधूरा प्रतीत होता है। अधिकारों की घोषणा और अनुभव की वास्तविकता के बीच का अंतर ही लैंगिक समानता की सबसे बड़ी चुनौती है।

इक्कीसवीं सदी ने महिलाओं की उपलब्धियों के अनेक नए अध्याय लिखे हैं। विज्ञान, शासन, व्यवसाय, शिक्षा और खेल-हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी क्षमता और नेतृत्व से स्थापित धारणाओं को बदला है। फिर भी प्रश्न बना रहता है कि क्या अवसरों की उपलब्धता मात्र से समानता सुनिश्चित हो जाती है, या वह तब साकार होती है जब सामाजिक और पारिवारिक संरचनाएँ भी उसे सहज रूप से स्वीकार करने लगीं।

किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं ने लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा तय की है और धीरे-धीरे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। फिर भी दिखाई देने वाली प्रगति हमेशा वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को प्रतिबिंबित नहीं करती।

आज महिलाएँ कार्यबल का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और साथ ही घर-परिवार की जिम्मेदारियाँ भी निभाती हैं। इसके बावजूद उनकी पूर्ण और समान भागीदारी अब भी सीमित है। पितृसत्तात्मक सोच, गहरे सामाजिक संस्कार और अवसरों तक असमान पहुँच वास्तविक सशक्तिकरण के मार्ग में बाधा बनते हैं। भारत में लैंगिक समानता का औपचारिक समर्थन व्यापक है। यह संविधान में निहित है, नीतिगत ढाँचों में समाहित है और संस्थागत प्रतिबद्धताओं द्वारा सुदृढ़ किया गया है। शिक्षा और नेतृत्व में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है तथा भेदभाव और उत्पीड़न के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा भी पहले से अधिक मजबूत हुई है। किन्तु सिद्धांत में हुई प्रगति हमेशा व्यवहार में समानता में परिवर्तित नहीं होती। अनेक महिलाओं के लिए समानता अब भी परिस्थितियों, संस्कृति और संदर्भ पर निर्भर रहती है।

व्यावसायिक क्षेत्रों में औपचारिक समानता अक्सर अनौपचारिक पूर्वाग्रहों के साथ सह-अस्तित्व में रहती है। भर्ती नीतियाँ भले ही लैंगिक रूप से तटस्थ हों, पर करियर के महत्वपूर्ण चरणों पर नेतृत्व की राह महिलाओं के लिए संकरी हो जाती है। प्रदर्शन के मानक समान दिखते हैं, फिर भी महिलाओं को अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए अक्सर अधिक प्रयास करना पड़ता है।

इसका संघर्ष प्रभाव गहरा होता है, निरंतर थकावट, सीमित अवकाश, करियर में रुकावट और दीर्घकालिक तनाव धीरे-धीरे सामान्य बन जाते हैं। यह अपेक्षा कि महिलाएँ पेशेवर जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करें और साथ ही आदर्श धरेलू भूमिकाएँ भी निभाएँ, एक मौन किंतु स्थायी दबाव उत्पन्न करती है। समानता का आकलन केवल प्रतिनिधित्व या शिक्षा तक पहुँच से नहीं किया जा सकता। उसे दैनिक जीवन को वास्तविकताओं में भी दिखाई देना चाहिए, परिवार में आपात स्थिति आने पर कार्य-समय कौन बदलता है,

पदोन्नति का अवसर कौन छोड़ देता है, या करियर के लिए स्थानांतरण कौन करता है। यही प्रश्न औपचारिक अधिकारों और वास्तविक समानता के बीच के अंतर को उजागर करते हैं। सांस्कृतिक अपेक्षाएँ भी इस असंतुलन को मजबूत करती हैं। समाज सफल महिलाओं का सम्मान तो करता है, पर उनकी प्राथमिक पहचान अब भी देखभाल करने वाली के रूप में देखी जाती है। एक सफल पुरुष से शायद ही कभी उसके घरेलू दायित्वों के बारे में पूछा जाता है, जबकि एक सफल महिला से अक्सर पूछा जाता है कि वह सब कुछ कैसे संभालती है। कार्यस्थलों पर लचीले कार्य-समय, अभिभावकीय अवकाश और बाल-देखभाल सुविधाओं जैसे सुधारों पर चर्चा बढ़ी है। परंतु केवल नीतियाँ पर्याप्त नहीं हैं। सांस्कृतिक स्वीकृति और ईमानदार क्रियान्वयन के बिना लचीलापन प्रतीकात्मक ही रह जाता है। लैंगिक समानता के पक्ष में आर्थिक तर्क भी मजबूत हैं। कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी उत्पादकता, पारिवारिक आय और दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास को सुदृढ़ करती है। परंतु समानता केवल आर्थिक रणनीति नहीं, बल्कि न्याय और गरिमा का प्रश्न भी है।

सच्ची प्रगति के लिए साझा जिम्मेदारी आवश्यक है। संस्थानों को पारदर्शी पदोन्नति प्रक्रियाएँ सुनिश्चित करनी होंगी, भेदभाव-विरोधी कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करना होगा और समावेशी कार्य-संस्कृति विकसित करनी होगी। समाज को उन मान्यताओं को चुनौती देनी होगी जो पुरुषत्व के केवल कमाने और स्त्रीत्व को केवल देखभाल से जोड़ती हैं। परिवारों के भीतर ही जिम्मेदारियों का न्यायपूर्ण बँटवारा

आवश्यक है। इस परिवर्तन में पुरुषों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। लैंगिक समानता केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है; यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है। वास्तविक परिवर्तन तब होगा जब समानता असाधारण दृढ़ता की मांग करना बंद कर देगी, जब जिम्मेदारियाँ स्वाभाविक रूप से साझा होंगी, करियर में विराम स्थायी हानि का कारण नहीं बनेगा और सम्मान बार-बार सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। प्रगति हुई है, पर यात्रा अभी अधूरी है। समानता की दिशा में उल्लेखनीय कदम अवश्य उठे हैं, किंतु वास्तविक परिवर्तन तब होगा जब समानता को सिद्ध करने या उसके लिए निरंतर संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब घर और कार्यस्थल दोनों में अवसर, सम्मान और जिम्मेदारियाँ स्वाभाविक रूप से साझा होंगी, तब लैंगिक समानता केवल नीतियों या घोषणाओं का विषय नहीं रहेगी, बल्कि जीवन की सामान्य और स्वीकृत व्यवस्था बन जाएगी।

उस दिन समाज की प्रगति का मापदंड यह नहीं होगा कि महिलाओं ने कितनी बाधाएँ पार कीं, बल्कि यह होगा कि उन्हें बाधाओं का सामना करना ही क्यों नहीं पड़ा। तब यह प्रश्न भी अप्रासंगिक ही जाएगा कि समाज लैंगिक समानता की दिशा में कितना आगे बढ़ा है, क्योंकि समानता स्वयं जीवन की स्वाभाविक वास्तविकता बन चुकी होगी।

समानता तब पूर्ण होगी जब अवसर, सम्मान और जिम्मेदारियाँ किसी सिद्धांत के कारण नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से साझा होंगी।

-अलका सक्सेना,
अतिरिक्त निदेशक जनसंपर्क
(सेवानिवृत्त)

सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वक्तव्य : आचार संहिता अब अनिवार्य क्यों?



सुनील दत्त गोयल

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी संस्थाएँ होती हैं - और इन संस्थाओं की साख उनके पदाधिकारियों के आचरण से तय होती है। न्यायापालिका, प्रशासन और आर्थिक नियामक संस्थाएँ देश की रीढ़ मानी जाती हैं। लेकिन बीते कुछ वर्षों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति उभरकर सामने आई है, जहाँ सार्वजनिक पदों पर बैठे माननीय और महामहिम व्यक्ति अपने दायित्वों की मर्यादा लांघते हुए ऐसे वक्तव्य और टिप्पणियाँ कर रहे हैं, जिनका दूरगामी और नकारात्मक प्रभाव समाज, न्याय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।

न्यायालयों से बाहर जाती टिप्पणियाँ और गिरती न्यायिक गरिमा : यह एक खुला सत्य है कि हमारे उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीश - चाहे वे सर्वोच्च न्यायालय में हों या विभिन्न उच्च न्यायालयों में - कभी-कभी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ऐसी टिप्पणियाँ कर बैठते हैं जो न तो आवश्यक होती हैं और न ही रिपोर्टिंग का हिस्सा बनती हैं। इससे भी अधिक गंभीर स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब यही न्यायाधीश

अदालत से बाहर सामाजिक कार्यक्रमों, सेमिनारों या सार्वजनिक मंचों पर व्यक्तिगत भावनाएँ व्यक्त करने लगते हैं।

भले ही यह अनजाने में हो या जानबूझकर - पर इसका असर न्याय व्यवस्था पर पड़ता है। निचली अदालतों में कार्यरत न्यायिक अधिकारी, विशेषकर मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी, कई बार यह मान लेते हैं कि ऊपर से यही संदेश है, और उसी मानसिकता के साथ वे अपने निर्णय देने लगते हैं। यह स्थिति न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता दोनों के लिए अत्यंत घातक है। न्याय का मूल सिद्धांत यही है कि फैसला केवल तथ्यों, साक्ष्यों और कानूनों के आधार पर हो - न कि किसी वरिष्ठ की टिप्पणी या भावनात्मक संकेत के प्रभाव में।

स्थानीय नियुक्तियाँ और निष्पक्षता पर प्रश्न

एक और संवेदनशील विषय है न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया। जब कोई वकील वर्षों तक किसी राज्य या जिले में प्रैक्टिस करता है और बाद में उसी क्षेत्र में न्यायाधीश बना दिया जाता है, तो यह मान लेना भोलेपन से कम नहीं कि वह अपने पुराने सामाजिक, पेशेवर या व्यक्तिगत संबंधों से पूरी तरह मुक्त रह पाएगा।

न्यायाधीशों की मृत्यु होते हैं। वे भी उसी समाज में रहते हैं, उसी समाज में सेवानिवृत्ति के बाद जीवन व्यतीत करते हैं। यही कारण है कि प्रशासनिक सेवाओं - जैसे केन्द्रीय एवं राज्य सेवाओं में यह सुनिश्चित किया जाता है कि अधिकारी को उसके गृह जिले में पोस्टिंग न मिले। ठीक यही सिद्धांत न्यायापालिका में भी लागू होना चाहिए यदि यह माना जाता है कि एक

कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी अपने गृह क्षेत्र में नियुक्त नहीं रह सकता, तो यह मान लेना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इससे अछूते रहेंगे - एक स्पष्ट दोहरा मानदंड है।

विशेष अदालतें: समाधान या नई समस्या?

उत्पीड़न से जुड़े मामलों - विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं से संबंधित मामलों - में एक ओर जटिल समस्या सामने आती है। कई बार जाँच में यह पाया गया है कि शिकायत झूठी या तथ्यहीन थी। इसके बावजूद न तो निर्दोष व्यक्ति को कोई मुआवजा मिलता है, न उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा की बरपाई होती है। उल्टे, झूठी शिकायत करने वाला व्यक्ति बेखौफ घूमता रहता है। ऐसे मामलों में यदि शिकायत गलत सिद्ध हो जाए, तो शिकायतकर्ता पर कठोर आर्थिक दंड और दंडात्मक कार्रवाई अनिवार्य होनी चाहिए अन्यथा न्यायालयों में मामलों का अंबाद इसी तरह बढ़ता रहेगा।

दूसरी ओर, विशेष अदालतों और विशेष न्यायाधीशों की व्यवस्था भी कई सवाल खड़े करती है। जब यह कहा जाता है कि महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई केवल महिला न्यायिक अधिकारी करेंगी, या अनुसूचित जाति-जनजाति मामलों के लिए अलग अदालतें होंगी, तो इसका अप्रत्यक्ष संदेश यही जाता है कि सामान्य न्यायाधीश निष्पक्ष नहीं हो सकते। यदि न्यायापालिका स्वयं अपने अधिकारियों पर पूर्ण विश्वास नहीं दिखा पा रही, तो आम जनता से भरोसे की उम्मीद कैसे की जा सकती है? यह व्यवस्था सामाजिक विभाजन और मानसिक दूरी को भी बढ़ावा देती है,

जबकि न्याय का सिद्धांत समानता पर आधारित होना चाहिए। आजादी के लगभग 80 वर्ष बाद यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है कि क्या अब भी हमें जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर अलग-अलग न्यायिक ढाँचों की आवश्यकता है?

आर्थिक नीतियाँ और गैर-जिम्मेदार वक्तव्य

विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं से संबंधित मामलों - में एक ओर जटिल समस्या सामने आती है। कई बार जाँच में यह पाया गया है कि शिकायत झूठी या तथ्यहीन थी। इसके बावजूद न तो निर्दोष व्यक्ति को कोई मुआवजा मिलता है, न उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा की बरपाई होती है। उल्टे, झूठी शिकायत करने वाला व्यक्ति बेखौफ घूमता रहता है। ऐसे मामलों में यदि शिकायत गलत सिद्ध हो जाए, तो शिकायतकर्ता पर कठोर आर्थिक दंड और दंडात्मक कार्रवाई अनिवार्य होनी चाहिए अन्यथा न्यायालयों में मामलों का अंबाद इसी तरह बढ़ता रहेगा।

दूसरी ओर, विशेष अदालतों और विशेष न्यायाधीशों की व्यवस्था भी कई सवाल खड़े करती है। जब यह कहा जाता है कि महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई केवल महिला न्यायिक अधिकारी करेंगी, या अनुसूचित जाति-जनजाति मामलों के लिए अलग अदालतें होंगी, तो इसका अप्रत्यक्ष संदेश यही जाता है कि सामान्य न्यायाधीश निष्पक्ष नहीं हो सकते। यदि न्यायापालिका स्वयं अपने अधिकारियों पर पूर्ण विश्वास नहीं दिखा पा रही, तो आम जनता से भरोसे की उम्मीद कैसे की जा सकती है? यह व्यवस्था सामाजिक विभाजन और मानसिक दूरी को भी बढ़ावा देती है,

जबकि न्याय का सिद्धांत समानता पर आधारित होना चाहिए। आजादी के लगभग 80 वर्ष बाद यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है कि क्या अब भी हमें जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर अलग-अलग न्यायिक ढाँचों की आवश्यकता है? आर्थिक नीतियाँ और गैर-जिम्मेदार वक्तव्य

विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं से संबंधित मामलों - में एक ओर जटिल समस्या सामने आती है। कई बार जाँच में यह पाया गया है कि शिकायत झूठी या तथ्यहीन थी। इसके बावजूद न तो निर्दोष व्यक्ति को कोई मुआवजा मिलता है, न उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा की बरपाई होती है। उल्टे, झूठी शिकायत करने वाला व्यक्ति बेखौफ घूमता रहता है। ऐसे मामलों में यदि शिकायत गलत सिद्ध हो जाए, तो शिकायतकर्ता पर कठोर आर्थिक दंड और दंडात्मक कार्रवाई अनिवार्य होनी चाहिए अन्यथा न्यायालयों में मामलों का अंबाद इसी तरह बढ़ता रहेगा।

माध्यम नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर है। इसके उतार-चढ़ाव करोड़ों लोगों की बचत, मेहनत और भविष्य से जुड़े हैं। इसी तरह, न्यायपालिका केवल फैसले देने की संस्था नहीं, बल्कि नागरिकों के विश्वास की अंतिम शरण है। हालाँकि पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाओं में कमी आई है, लेकिन यह प्रवृत्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

अतः मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह सभी सार्वजनिक पदों पर बैठे नेताओं और अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दे कि वे ऐसे कोई सार्वजनिक वक्तव्य न दें, जिनसे शेर बाजार, सामाजिक व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली या किसी भी प्रकार की हिंसक अथवा अहिंसक घटना या दुर्घटना को बढ़ावा मिले - क्योंकि आम व्यक्ति इन सब से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है।

इसलिए अब समय आ गया है कि सरकार और न्यायापालिका दोनों मिलकर यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्ति बिना सोचे-समझे कोई वक्तव्य न दें। एक स्पष्ट, लिखित और सख्त आचार-संहिता लागू हो - चाहे वह न्यायाधीश हों, न्यायिक संस्थाओं के प्रमुख हों या राजनेता।

न्याय तभी सार्थक है जब वह निष्पक्ष हो और दिखे भी निष्पक्ष। और अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होती है, जब उस पर भरोसा अडिग रहे। यही संविधान की आत्मा है और यही लोकतंत्र की सच्ची परीक्षा।

-रोयल्टन सुनील दत्त गोयल, महाविदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।

राशिफल शनिवार 7 मार्च, 2026

चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत् 2082, चित्रा नक्षत्र दिन 11:16 तक, वृद्धि योग प्रातः 6:52 तक, बालव करण साय 7:18 तक, चन्द्रमा आज तुला राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-तुला, मंगल-कुम्भ, बुध-कुम्भ, गुरु-मिथुन, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह आज सर्वार्थ सिद्धि योग दिन 11:16 से सूर्योदय तक है। भद्रा प्रातः 5:29 से सायं 5:54 तक रहेगी। आज कल्पादि, चतुर्थी व्रत है। श्रेष्ठ चौघडिया: शुभ 8:16 से 9:44 तक, चर 12:38 से 2:05 तक, लाभ-अमृत 2:05 से 5:00 तक। राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 6:49, सूर्यास्त 6:27

मेघ	सिंह	धनु
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा।	व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।	आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

वृष	कन्या	मकर
मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।	व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटक हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन	तुला	कुंभ
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरिपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। धार्मिक स्थान की यात्रा सभव है।	मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति ठीक रहेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आवश्यक कार्य योजनासुसार बने लगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बने लगे। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

कर्क	वृश्चिक	मीन
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।	घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागवौड़ रहेगी। आज मन में असंतोष बना रहेगा। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।	चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

विश्व शांति के लिए पुष्कर में 43 दिवसीय "शत गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ" कल से

महायज्ञ के लिए खेरकड़ी रोड पर लगभग 80 बीघा क्षेत्र में भव्य यज्ञनगरी विकसित की गई है

पुष्कर, (निसं) विश्वभर में बढ़ते जुद्ध जैसे हालात, अंतरराष्ट्रीय तनाव और अस्थिरता के बीच भारत की आध्यात्मिक परंपरा से विश्व शांति के लिए एक बड़ी पहल होने जा रही है। तीर्थराज पुष्कर में 8 मार्च से 19 अप्रैल तक 43 दिवसीय "शत गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ" आयोजित किया जाएगा, जिसमें 3 करोड़ आहुतियाँ और 24 करोड़ गायत्री मंत्र जाप के माध्यम से वैश्विक संतुलन और शांति की कामना की जाएगी।

महा निर्माणी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज के सांघि में होने वाले इस महायज्ञ की तैयारियाँ लाभग एक वर्ष पूर्व ही शुरू हो गई थी। स्वामी प्रखर महाराज ने

महायज्ञ में 3 करोड़ आहुतियाँ और 24 करोड़ गायत्री मंत्र जाप के माध्यम से वैश्विक संतुलन और शांति की कामना की जाएगी

वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को पहले से ही भांपते हुए इस महायज्ञ का संकल्प लिया था। करपात्री महाराज के प्रमुख शिष्य स्वामी प्रखर महाराज के मार्गदर्शन में आयोजित यह महायज्ञ विप्र फाउंडेशन और श्री प्रखर पुरोचक्र के माध्यम से वैश्विक संतुलन और शांति की कामना की जाएगी।

स्वामी प्रखर महाराज का भी कहना है कि शास्त्रों में महायज्ञों के प्रभाव से सुष्ठु-संतुलन और कल्याण का वर्णन मिलता है तो वर्तमान संघर्षपूर्ण वातावरण में आध्यात्मिक साधनों के माध्यम से शांति का मार्ग भी प्रशस्त किया जा सकता है। महायज्ञ आयोजन समिति के मुख्य संरक्षक तिलक राज शर्मा ने बताया कि महायज्ञ के लिए शास्त्रीय मानकों के अनुरूप 200 हवन कुंडों का निर्माण किया गया है। इन कुंडों में लगभग 3 करोड़ आहुतियाँ अर्पित की

जाएंगी, जबकि महायज्ञ स्थल पर 2000 से अधिक साधक 24 करोड़ गायत्री मंत्रों का जाप करेंगे। आयोजन समिति के अध्यक्ष राधेश्याम गुरुजी ने बताया कि हवन कुंड केवल अग्नि देवियों नहीं, बल्कि मां भगवती का मुख माने जाते हैं। महायज्ञ में प्रयुक्त हवन सामग्री से लेकर संपूर्ण विधि-विधान पूर्णतः शास्त्र समतल रखा गया है। यज्ञ में 200 चयनित ब्राह्मण दंपति बैठेंगे उन्हें भी विधिवत प्रायश्चित्त व संकल्प कराया गया है। वहीं 2000 से अधिक साधकों का चयन भी साक्षात्कार प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। आयोजन समिति के कोषाध्यक्ष अशोक जोशी ने बताया कि महायज्ञ का विधिवत शुभारंभ 8 मार्च को सायं 4

बजे भव्य शोभायात्रा के साथ होगा। महायज्ञ के लिए खेरकड़ी रोड पर लगभग 80 बीघा क्षेत्र में भव्य यज्ञनगरी विकसित की गई है, जो आगामी 43 दिनों तक साधना, जाप और विश्व कल्याण के संकल्प का केंद्र बनेगी। महायज्ञ संचालक मंडल के सदस्य नवीन शर्मा के अनुसार वर्तमान वैश्विक संघर्ष की घुड़पुर्ण में भारत की आध्यात्मिक परंपरा से प्र

स्वदेशी की ताकत से भारत बनेगा दुनिया की महाशक्ति : भजनलाल शर्मा

प्रधानमंत्री मोदी का "मेक इन इंडिया" का उद्घोष बना आत्मनिर्भर भारत का आह्वान : मुख्यमंत्री

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वदेशी हमारी संस्कृति का हिस्सा है और यह हमारी समातन परंपरा है। स्वदेशी की इसी ताकत से हमारा देश आत्मनिर्भर बनने के साथ ही दुनिया की महाशक्ति बनेगा। शर्मा शुक्रवार को जगतपुर में स्वदेशी जागरण मंच के उद्यमी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी और स्वावलंबन भारत की आत्मा में हजारों वर्षों से समाए हुए हैं। सदियों पहले जब यूरोप के देश व्यापार के नाम पर दुनिया में भटक रहे थे, तब भारत के मुर्शिदाबाद की मलमल, बनारस का रेशम, राजस्थान की लहरिया और बंधेज पूरी दुनिया के बाजारों की शान थे। उन्होंने कहा कि इसी पहचान और आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी जागरण मंच लगातार परिश्रम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड का उद्घोष कर पुनर्जागरण का आह्वान किया है। कोरोना के समय हमारे देश ने दुनिया के कई देशों को दवाइयां और वैक्सिन भेजी। यह आत्मनिर्भर भारत की ताकत थी और प्रधानमंत्री की उस सोच का परिणाम भी जिसने भारत को उपभोक्ता से उत्पादक बनाने का कार्य किया था। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच के सहयोग और कार्यों से देश



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जगतपुर में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से आयोजित उद्यमी सम्मान समारोह में भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया।

आत्मनिर्भरता में आगे बढ़ रहा है। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। विश्व में देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है। आज भारत रक्षा क्षेत्र से लेकर सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। यह प्रधानमंत्री की नीतियों, दृढ़ इच्छाशक्ति और देशवासियों की

मेहनत का ही फल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े उद्योगों के साथ ही छोटे एवं स्थानीय उद्यमियोंसे आत्मनिर्भरता आती है। यही स्वदेशी की आत्मा और ग्रामीणों की ताकत है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की खरीददारी से उस उत्पाद से जुड़ी पूरी श्रृंखला को सहारा मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए

पंच गौरव कार्यक्रम लागू किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले वर्ष में ही राईजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। जिसके तहत 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश एमओयू हुए। इनमें से 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हस्तशिल्प कला भी हमारी पहचान है, जिसके

■ भजनलाल शर्मा ने कहा कि "सदियों पहले जब यूरोप के देश व्यापार के नाम पर दुनिया में भटक रहे थे, तब भारत के मुर्शिदाबाद की मलमल, बनारस का रेशम, राजस्थान की लहरिया और बंधेज पूरी दुनिया के बाजारों की शान थे।"

उत्पादों की विश्व में मांग है। वहीं किले, महल, अभ्यारण्य और मंदिरों से हमारा पर्यटन क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी की हवेलियों हमारी धरोहर है। हमारी सरकार इन हवेलियों को चिन्हित करते हुए इनके संरक्षण का काम कर रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक आर. सुंदरम, राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल, अखिल भारतीय महिला प्रमुख अर्चना मीणा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर प्रांत के संघचालक महेन्द्र सिंह मगगोसहित प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।

राजस्थान विधानसभा में पारित हुआ "डिस्टर्ब एरिया बिल"

दंगा-सांप्रदायिक तनाव वाले इलाकों में एडीएम-एसडीएम की मंजूरी के बिना प्रॉपर्टी खरीद-बेच नहीं सकेंगे

-विधानसभा संवाददाता-
जयपुर। विधानसभा में शुक्रवार को बहस के बाद डिस्टर्ब एरिया बिल पारित कर दिया गया। "दराजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमुवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फोर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेन्ट्स फ्रॉम एक्विजिशन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब एरियाज बिल, 2026" के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार दंगा प्रभावित इलाकों को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकेगी। डिस्टर्ब एरिया में एडीएम या एसडीएम की मंजूरी के बिना कोई भी प्रॉपर्टी की खरीद और बेचान नहीं हो सकेगा, न रजिस्ट्री हो सकेगी।

बिल के प्रावधानों के अनुसार, दंगा प्रभावित और जनसंख्या असंतुलन से हिंसा के हालात बनने पर एक क्षेत्र, कॉलोनी या वार्ड को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाएगा। क्षेत्र विशेष को डिस्टर्ब एरिया घोषित किए जाने के बाद वहां एडीएम-एसडीएम की मंजूरी के बिना प्रॉपर्टी की खरीद-बेचान नहीं किया जा सकेगा। बिना अनुमति अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो भी जाता है तो उसे अमान्य कर शून्य घोषित किया जा सकेगा। बिल में समुदाय विशेष की जनसंख्या बढ़ने और डेमोग्राफी प्रभावित होना भी डिस्टर्ब एरिया घोषित करने का आधार बन सकता है।

बाजार दर से कम पर प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी

ऐसे इलाकों में एडीएम-एसडीएम से मंजूरी मिलने के बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकेगी। डिस्टर्ब एरिया में एडीएम-एसडीएम संबंधित प्रॉपर्टी के बारे में पूरी रिपोर्ट ली जाएगी। अफसर यह सुनिश्चित करेंगे कि बाजार कीमत से कम में प्रॉपर्टी नहीं बिके। किसी दबाव में या स्थानीय लोगों के दबाव में प्रॉपर्टी नहीं बिके यह भी जांच होगी। डिस्टर्ब एरिया में एडीएम-एसडीएम प्रॉपर्टी खरीद-बेचाने के आवेदन पर 3 महीने में फैसला करेंगे, इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकेगा।

कानून के उल्लंघन पर सजा व जुर्माना

राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन पर 3 से

■ बिल के प्रावधानों के मुताबिक एडीएम-एसडीएम की मंजूरी के बिना अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो भी जाता है तो उसे अमान्य कर शून्य घोषित किया जा सकेगा।

■ इस बिल में समुदाय विशेष की जनसंख्या बढ़ने और डेमोग्राफी प्रभावित होना भी डिस्टर्ब एरिया घोषित करने का आधार बन सकता है। हालांकि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास गिरवी प्रॉपर्टी पर कानून लागू नहीं होगा।

5 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना कानून के इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होगा, जिसमें 3 साल से 5 साल तक जेल और जुर्माने की सजा होगी। साथ ही 1 लाख तक जुर्माना भी लगाया जाएगा। हालांकि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रॉपर्टी गिरवी होने पर यह कानून लागू नहीं होगा। डिस्टर्ब एरिया में गिरवी प्रॉपर्टीज को बैंक और एनबीएफसी नीलाम कर सकेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री एवं कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि, दंगे नहीं तो डिस्टर्ब एरिया घोषित नहीं होगा। प्रॉपर्टी का बाजार मूल्य मिल रहा है या नहीं, बाजार मूल्य से कम नहीं मिले। अफसर यह देखेंगे कि प्रॉपर्टी बाजार मूल्य से कम में नहीं मिले। यह कानून कमजोर लोगों को रक्षा करता है। पटेल ने कहा कि जोधपुर में एक ऐसा भी क्षेत्र है, जहां कोई घुस नहीं सकता। राजस्थान में ऐसे क्षेत्र लगातार बढ़ रहे हैं।

कांग्रेस सत्ता में आई तो खत्म करेंगे कानून : डोटासरा

जयपुर (विंस)। डिस्टर्ब एरिया बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में कहा कि, "2028 में कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इस बिल को खत्म करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि, सरकार धार्मिक उन्माद फैलाकर ऐसे बिल लाकर बहुसंख्यक वोटों को अपनी तरफ करके गुजरात का मांडल यहां पर अपनाते जा रही है। जमीन जायदाद पर सरकार की नजर है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। संपत्ति खोद बेचने के अधिकार संविधान से हमें मिले हैं। इस पर सरकार का नियंत्रण करना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए शांत क्षेत्र को अर्शात करने का षड्यंत्र है।"

डोटासरा ने कहा कि डिस्टर्ब एरिया कानून सा होगा, समुदाय विशेष कानून सा होगा जिससे डिस्टर्ब करना चाहते हैं? 2028 में कांग्रेस सत्ता में आएगी, हम इस बिल को खत्म करेंगे। राजस्थान में यह परंपरा है, अगली बार हम आएंगे। राजस्थान में आपकी सरकार है फिर भी ऐसा बिल लाकर राजस्थान को क्यों जलाना चाह रहे हो। डोटासरा ने कहा कि इस बिल के जरिए आप समुदाय विशेष को इंगित करना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है? कानून में मंशा स्पष्ट करनी पड़ेगी, जो नहीं की गई है। इस बिल की धारा 5 में जिस तरह के प्रावधान हैं, उससे भ्रष्टाचार के दरवाजे खुल जाएंगे। कोर्ट में भी नहीं जा सकेगा।

बूंदी के कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने तो बहस के दौरान यहां तक कह दिया कि, "अगर राजस्थान में सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उसकी जिम्मेदार मौजूदा सरकार होगी।" उनका इस टिप्पणी के बाद सदन में माहौल गर्मा उठा, मंत्री अविनाश गहलोत और पूर्व मंत्री श्रीचंद कुलानी समेत मंत्री के तमाम विधायकों ने उनके बयान पर कड़ी नाराजगी जताई।

डेगाना में दरी पट्टियों की खरीद पर सदन में हंगामा

शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निलंबित करते हुए पूरे प्रकरण की जांच की घोषणा की

-विधानसभा संवाददाता-
जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दों पर तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला। सबसे ज्यादा चर्चा डेगाना विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में दरी पट्टियों की खरीद को लेकर हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तत्कालीन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को निलंबित करने के आदेश देते हुए पूरे प्रकरण की जांच कराने की घोषणा की। प्रश्नकाल के दौरान डेगाना से विधायक अजय सिंह किलक ने भेरुंडा क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में दरी वितरण में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां अधिक दरी की जरूरत थी, वहां कम दरियां खरीदी गईं और वितरण में भी गड़बड़ी हुई।

किलक ने बताया कि वर्ष 2022-23 में विधायक कोष से 399 दरी पट्टियां वितरित करने का दवा किया गया था, लेकिन भेरुंडा सीबीओ ब्लॉक में 171 दरियां ही जानी थीं, जबकि केवल 104 ही दी गईं। उन्होंने कहा कि करीब 5 लाख रुपये से अधिक कीमत की दरियां अब तक वितरित नहीं हुई हैं। इस संबंध में उन्होंने 17 दिसंबर 2022 का एक रिपोर्ट पत्र भी सदन में पेश करने की बात कही, जिस पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भेरुंडा के प्रधानाचार्य और स्टोर इंचार्ज के हस्ताक्षर हैं। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि कई स्कूलों में जहां 200 से 300 छात्रों का नामांकन है, वहां केवल 10-15 फीट की एक दरी दी गई, जबकि कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहां नामांकन बहुत कम था शून्य है, वहां भी एक-एक दरी भेज दी गई। इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि दरी पट्टियों की खरीद में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं और इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि यह मामला पिछली कांग्रेस सरकार के समय का है और उस दौरान सरकारी धन की लूट हुई है। मंत्री ने मामले की जांच के आदेश देते हुए तत्कालीन बीईओ को निलंबित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि करीब 35 लाख रुपये की दरियां खरीदी गई थीं। उस समय के विधायक की सिफारिश पर स्कूलों के लिए दरी पट्टियां देने की बात थी, लेकिन बाद में उनकी जगह फर्श खरीदी गए। रिपोर्ट के अनुसार 288 फर्श स्कूलों तक पहुंचे, जबकि 171 फर्श का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। मदन दिलावर ने आरोप लगाया कि उस समय के विधायक विजयपाल मिश्रा के कार्यकाल में जिन शिक्षकों ने दरी लेने से मना किया, उनके तबादले तक करवा दिए गए थे। इस पर उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने सवाल उठाया कि यदि संबंधित अब धाजपा में शामिल है तो क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी भ्रष्टाचार पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर और एसपी ने क्या कोर्ट को पोस्ट ऑफिस समझ रखा है : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पैरोल प्रार्थना पत्रों को लापरवाही से खारिज करने से जुड़े मामले में भरतपुर कलेक्टर और एसपी पर नाराजगी प्रकट की। अदालत ने कहा कि आप लोगों ने कोर्ट को क्या पोस्ट ऑफिस समझ रखा है। आपके इसी रवैये के चलते कोर्ट में पैरोल से जुड़े प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं और हम जरूरी मामलों की सुनवाई नहीं कर पाते हैं। जस्टिस महेन्द्र गोयल व जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह टिप्पणी शुक्रवार को अनिल कपूर उर्फ रिंकू की याचिका पर सुनवाई करते हुए की।

सुनवाई के दौरान अदालत आदेश की पालना में भरतपुर कलेक्टर व एसपी कोर्ट में हाजिर हुए। अदालत ने दोनों अफसरों को कहा कि वे इन मामलों में अपना महत्वपूर्ण काम में क्यों नहीं लेते हैं। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता कैदी 12 साल की सजा काट चुका है और वह पिछले 4 साल से ओपन जेल में है, लेकिन एक पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पर आप लोगों ने भरोसा कर लिया। आपने अपना महत्वपूर्ण इस्तेमाल नहीं किया। यदि आप किसी चीज को लेकर आशंका जता रहे हैं तो उसके ठोस सबूत भी पेश करें। वहीं

कलेक्टर की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता की 20 दिन की पैरोल मंजूर कर ली गई है। इसके साथ ही एसपीस गृह और डीजीपी की ओर से विधानसभा सत्र में व्यस्त होने का हवाला देते हुए उपस्थिति से छूट चाही। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि कई बार दोनों अफसरों को इस व्यवस्था में सुधार के लिए कहा जा चुका है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे में वे 16 मार्च को पेश होकर इस लापरवाही पूर्ण रवैये पर अपना स्पष्टीकरण दें और साथ ही भविष्य में ऐसी

लापरवाही से बचने के उपायों के बारे में भी बताएं। मामले से जुड़े अधिकता गोविंद प्रसाद रावत ने बताया कि याचिकाकर्ता कैदी का आचरण संतोषजनक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भरतपुर के संयुक्त निदेशक ने भी रिपोर्ट में पैरोल देने की सिफारिश की थी, लेकिन भरतपुर एसपी की रिपोर्ट पर उसे पैरोल नहीं दी गई। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चारों अफसरों को तलब करते हुए याचिकाकर्ता के पैरोल पर विचार करने को कहा था।

भट्टा बस्ती में जुमे की नमाज के दौरान ढही मस्जिद की दीवार, 15 नमाजी घायल हुए

छह लोगों की हालत गंभीर, घायलों को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राजधानी के भट्टा बस्ती थाना इलाके में स्थित फिरदौस मस्जिद में शुक्रवार दोपहर जुमे की नमाज के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मस्जिद की एक दीवार अचानक भरभराकर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से करीब पंद्रह नमाजी घायल हो गए। हादसे के समय मस्जिद में सैकड़ों लोग मौजूद थे। दीवार गिरते ही मस्जिद परिसर में अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार सुनाई देने लगी। एडिशनल डीसीपी नार्थ बजरंग सिंह



भट्टा बस्ती इलाके में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद की दीवार ढहने से एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।



■ चीख-पुकार के बीच लोगों ने खुद शुरू किया रेस्क्यू, मलबे से लोगों को बाहर निकाला

■ हादसे की सूचना पर भट्टा बस्ती पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया

शेखावत ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे जुमे की नमाज समाप्त होने के बाद कुछ नमाजी मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, जबकि कुछ लोग वजुखाने के पास भीड़ कम होने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान अचानक दीवार का एक हिस्सा ढह गया और वहां खड़े लोग मलबे की चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद नमाजियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और मलबा हटाकर घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद

घायलों को ई-रिक्शा, ट्राई साइकिल और अन्य वाहनों की मदद से तुरंत कांबटिया अस्पताल पहुंचाया गया। भीड़ अधिक होने के कारण राहत कार्य में कुछ देर तक मुश्किल भी आई, लेकिन स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी घायलों को जल्द अस्पताल पहुंचा दिया गया। कांबटिया अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आर.एस. तंवर ने बताया कि कुल 15 घायलों को अस्पताल लाया गया था। इनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल रेफर किया गया, जबकि मामूली चोट वाले लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं गंभीर घायलों में रस्तम (40), ईशान

(34), खुशींद (25), सुहैल (25), इमाम जफर (20) और इकबाल (18) शामिल हैं। एसएमएस अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेण्डेंट डॉ. जगदीश मोदी ने बताया कि 11 घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से तीन मरीज आईसीयू में भर्ती हैं, जबकि आठ का इलाज मास कैजुअल्टी वार्ड में चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही भट्टा बस्ती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस के अनुसार मस्जिद की दीवार का केवल एक हिस्सा गिरा है, जिससे बड़ा जानी नुकसान टल गया। प्रारंभिक जांचकर्ता ने दीवार के कमजोर होने और उस

पर अचानक अतिरिक्त दबाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की तकनीकी जांच कर रही है और सुरक्षा के सुपरिटेण्डेंट डॉ. जगदीश मोदी ने बताया कि 11 घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से तीन मरीज आईसीयू में सावधानी बरतने की अपील की। इधर घटना की जानकारी मिलने पर विधायक अमीन कागजी, विधायक हाकम अली और असरार कुरैशी भी विधानसभा से सीधे एसएमएस अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। फिरदौस मस्जिद कमेट्री से जुड़े लोगों का

कहना है कि जुमे की नमाज के बाद अचानक बच्चे भागने लगे तो दीवार पर अतिरिक्त लोड पड़ गया व दीवार गिर गई। जहां दीवार गिरी है। उस जगह चपलें उतारी जाती हैं, लेकिन लोग नमाज पढ़कर निकल रहे थे तो उन पर दीवार गिर गई। जयपुर शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आरआर तिवारी ने कहा कि ईश्वर का शुक है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। कुछ लोगों के चोट लगी, जिनका उपचार चल रहा है। गौरतलब है कि जुमे की नमाज का इस्लाम में विशेष महत्व है। इसी के चलते जुमे की नमाज पर अन्व दिनों के मुकाबले भीड़ ज्यादा होती है।

ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने जान दी

जयपुर। करघनी थाना इलाके में स्थित कनकपुरा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को एक युवक ने एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार युवक की पहचान करीब 35 वर्षीय युवक के रूप में हुई है। लेकिन

पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि युवक ने अचानक स्टेशन पर आ रही एक्सप्रेस ट्रेन के सामने छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्टेशन परिसर में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर करघनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे

में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से घटना के बारे में जानकारी भी जुटाई। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मृतक की पहचान और उसके परिजनों की जानकारी जुटाने के साथ ही पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है।

10 मार्च तक जारी रहेगी विधानसभा की कार्यवाही

जयपुर (विंस)। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही अब 10 मार्च तक चलेगी। शुक्रवार को स्पीकर वासुदेव देवानी की अध्यक्षता में हुई विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति (बीएससी) की बैठक में आगामी दिनों का कार्यक्रम तय किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 7 और 8 मार्च को विधानसभा की

छुट्टी रहेगी, जबकि 9 और 10 मार्च को महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा कर उन्हें पारित कराया जाएगा। 9 मार्च को सदन में राजस्थान पंचायतीराज संशोधन बिल-2026 और राजस्थान आयुर्वेद योग चिकित्सा विश्वविद्यालय बिल-2026 पर चर्चा होगी और बहस के बाद इन्हें पारित कराया जाएगा।

आई.ओ.आर.ए. इकोलोजिकल सोल्यूशन और कृषि विभाग के बीच सहमति बनी

जयपुर (कांस)। कृषि विभाग और आईओआरए इकोलोजिकल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के मध्य राजस्थान में एग्रीकल्चरल लैंड मैनेजमेंट कार्बन प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए सहमति हुई। इस प्रकार की गतिविधियों में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कैम 2023 के तहत राजस्थान के किसानों को सुगमता से

कार्बन फाइनेंस उपलब्ध कराने हेतु राज्य के चयनित ब्लॉकों में कार्बन उत्सर्जन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। इनमें कोटपुतली-बहरोडा का बानसपुर स्कूल, दौसा का महवा और टोंक का बालपुरा ब्लॉक शामिल है। किसानों को पायलट प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया एक आर्थिक और पर्यावरणीय तंत्र है।

से कृषकों को कुछ मात्रा में कार्बन फाइनेंस प्राप्त हो सकता है। इसे प्रदेश के तीन ब्लॉकों में प्रोवाबो बेसिस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है, जिसे जल्द ही पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। जिससे कृषकों को आय में वृद्धि होगी। कार्बन क्रेडिट जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए बनाया गया एक आर्थिक और पर्यावरणीय तंत्र है।

‘आर्मी डे परेड ने देशभक्ति व सैन्य गौरव की भावना को जन-जन तक पहुंचाया’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने सेना दिवस परेड -2026 संकलन पुस्तक व लघु फिल्म का विमोचन किया

जयपुर, 06 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 78वें सेना दिवस पर आयोजित हुई ऐतिहासिक आर्मी डे परेड ने भारतीय सेना और जनमानस के बीच सेतु बांधने का काम किया तथा इस परेड ने राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और सैन्य गौरव की भावना को जन-जन तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार आर्मी डे परेड का छावनी क्षेत्र के बाहर आम नागरिकों के बीच जयपुर में सम्पन्न होना हम सब के लिए गौरव की बात है।

शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जन भागीदारी ही किसी भी राष्ट्रीय उत्सव की असली शक्ति होती है। आर्मी डे परेड को आम लोगों ने अपने स्नेह और उत्साह से सफल बनाया।**



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 78वें सेना दिवस पर “आर्मी डे परेड संकलन” पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान सतशक्ति कमान के सेना कमाण्डर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास भी उपस्थित रहे।

कार्यालय में सेना दिवस परेड-2026 संकलन पुस्तक एवं लघु फिल्म के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी 2026 की तारीख राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गई है। भव्य और व्यापक आर्मी डे परेड आयोजित कर हमने राजस्थान में नई परंपरा की

शुरुआत की है। शर्मा ने कहा कि जनभागीदारी ही किसी भी राष्ट्रीय उत्सव की असली शक्ति होती है। आर्मी डे परेड को आम लोगों ने अपने स्नेह और उत्साह से सफल बनाया। उन्होंने इस परेड की सफलता को विभिन्न विभागों के समन्वय का परिणाम बताया। उन्होंने

भारतीय सेना के सभी सैनिकों और अधिकारियों का अभिनेदन किया और कहा कि सेना का अनुशासन व समर्पण राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है तथा उनके कठिन परिश्रम ने इस परेड को उत्कृष्ट बनाया।

शर्मा ने सेना दिवस परेड-2026 की संकलन पुस्तक एवं लघु फिल्म का

विमोचन किया। इस दौरान कार्यक्रम में लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, सतशक्ति कमान के सेना कमाण्डर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, विभिन्न विभागों के अधिकारी सहित, सेना के अधिकारी भी उपस्थित थे।

‘मैं कांग्रेस का राज्यसभा का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

घर की छत पर इसी पार्टी का झंडा फहराया करता था।

बाद में वे कांग्रेस में शामिल हुए और फिर के. राजू, एक पूर्व आईएस अधिकारी से मिले, जो सभी उमरों हुए दलितों के गॉडफादर हैं और राहुल गांधी के चारों ओर दलितों की एक दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, "दलितों के लिए, दलितों द्वारा, दलितों के साथ।"

ठीक है यह भी, लेकिन क्या राहुल गांधी कोई विचार नहीं करते, या क्या उनका विचार इतना अंधा है कि वे हर निर्णय को के.सी. वेणुगोपाल, के. राजू या "जय जगत" जैसे को सौंपते रहते हैं?

जय जगत अपनी ताकत दिखा रहा है और यह संकेत देना चाहता है कि वह पार्टी में निर्णयों को नियंत्रित कर रहा है और वह बांस है क्योंकि बांस उसके साथ है।

जय जगत ने तमिलनाडु की राज्यसभा सीट भी हासिल कर ली है, जो एक ईसाई दलित को मिली है, जो जय जगत से है और के. राजू द्वारा समर्थित है।

भाजपा ने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार को हरा देने के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार खड़ा किया है, जो बुनियादी तौर पर भाजपा से है, उसके पास ढेर सारा पैसा है और वह कांग्रेस के

■ **हरियाणा में राज्यसभा चुनाव का नतीजा इस सवाल का जवाब ढूंढने में शायद कुछ मदद करेगा।**

दलितों के नरेटिव को नियंत्रित करना चाहते हैं। वे पार्टी में स्थापित दलित नेताओं, जैसे उदय भान और अशोक तंवर को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते। वे एक नए व्यक्ति को चाहते थे, जिसे वह नियंत्रित कर सकें।

ठीक है यह भी, लेकिन क्या राहुल गांधी कोई विचार नहीं करते, या क्या उनका विचार इतना अंधा है कि वे हर निर्णय को के.सी. वेणुगोपाल, के. राजू या "जय जगत" जैसे को सौंपते रहते हैं?

जय जगत अपनी ताकत दिखा रहा है और यह संकेत देना चाहता है कि वह पार्टी में निर्णयों को नियंत्रित कर रहा है और वह बांस है क्योंकि बांस उसके साथ है।

जय जगत ने तमिलनाडु की राज्यसभा सीट भी हासिल कर ली है, जो एक ईसाई दलित को मिली है, जो जय जगत से है और के. राजू द्वारा समर्थित है।

भाजपा ने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार को हरा देने के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार खड़ा किया है, जो बुनियादी तौर पर भाजपा से है, उसके पास ढेर सारा पैसा है और वह कांग्रेस के

विधायकों को खरीदने के लिए तैयार है। क्या राहुल गांधी जीवन से कोई सबक नहीं सीखते? या क्या वे बस इस कारण से परवाह नहीं करते, क्योंकि वे इतने विशेषाधिकार प्राप्त हैं? हरियाणा का घटनाक्रम रोमांचक रहेगा, क्योंकि यहां पैसे, सत्ता, निराशा और गुस्से का खेल होगा।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खेड़ा ने कहा कि जब रूस भारत को तेल देने के लिए तैयार था, तब मोदी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन अमेरिका की अनुमति मिलने के बाद ही सरकार सक्रिय हुई। अमेरिका ने भारत को छूट दी है, जबकि छूट वहीं दी जाती है, जहां प्रतिबंध लागू होते हैं।

कोटा का डॉक्टर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सिविल सेवा के लिए चयनित किया गया था, जहां वे वर्तमान में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

स्व-अनुशासन और दृढ़ता में विश्वास रखने वाले अनुज ने अपनी तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग पर भरोसा किया और दिल्ली के "एचयोर" आईएसएस से इंटरव्यू गाइडेंस प्राप्त की।

साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले अनुज के पिता कोटा में न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करते हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं।

कुल 958 उम्मीदवारों ने आईएसएस, आईएसएस, आईपीएस और अन्य सेवाओं के लिए क्वालीफाई किया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइटों पर रोल नंबर के आधार पर परिणाम देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।

यूपीएससी ने एक बयान में कहा, "अंक, परिणाम की घोषणा के 15 दिनों के भीतर वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।"

लिखित सीएसई परीक्षा अगस्त 2025 में आयोजित की गई थी, जबकि व्यक्तिगत परीक्षाएं (पर्सनैलिटी टेस्ट) दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच हुआ था।

अनुज के अलावा प्रदेश के दस अन्य अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है। ये हैं, बहरोडी के तरुण चावड (49 वीं रैंक), बालोतरा के गौरव चोपड़ा (83 वीं रैंक), बूंदी के सौरभ शर्मा (146 वीं रैंक), तिजारा के निशांत यादव (237 वीं रैंक), बालोतरा के जितेंद्र प्रजापति (287 वीं रैंक), पोकरण के प्रदीप दानरत्न (499 वीं रैंक), सीकर के संजय कुमार (502 वीं रैंक), जयपुर के संभव पांडे (608 वीं रैंक), तिजारा के बादल यादव (665 वीं रैंक), दौसा के आशीष शर्मा (722 वीं रैंक)।

बिहार में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुनाव करो। इस संदर्भ में सीमा गुप्ता का नाम उछाला जा रहा है, जो संघ पृष्ठभूमि से बताई जाती है।

नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने के लिए ताकत जुटाने के बाद, यह निश्चित माना जा रहा है कि भाजपा अपने उम्मीदवार को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करेगी। हालांकि, यह भी संभव है कि कुमार के बेटे को सत्ता की राजनीति में लाया जाये और नई सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाया जाए।

राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में एक नया और अप्रत्याशित चेहरा चुनकर भाजपा यह राजनीतिक संदेश दे सकती है कि बिहार में पूरी तरह से नयी शुरुआत की जा रही है। इन परिदृश्यों में नई सरकार को भाजपा नेतृत्व का प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त भी माना जाएगा। वहीं, ऐसी सम्भावना नहीं है कि नेतृत्व जेडीयू की विभाजित करने की कोशिशों में लगेगी। हालांकि नीतीश कुमार जैसे किसी प्रभावशाली नेता के बिना पार्टी के पास लंबी अवधि तक अस्तित्व में रह पाना मुश्किल होगा। कुमार अब भी ईबीसी वर्ग में लोकप्रिय हैं और पिछले वर्षों में उन्होंने महिला वोटर्स में एक मजबूत समर्थन आधार बनाया है। भाजपा इन वर्गों का समर्थन खोना नहीं चाहेगी। इसलिए, यह संभावना है कि भाजपा नेतृत्व कुमार के साथ सदाशयतापूर्ण और सुलझे हुये तरीके से ही पेश आएगा। इसके साथ ही, यह भी संभावना है कि समाजवादी पृष्ठभूमि के चलते बिहार में हिंदुत्व के कट्टर संस्करण को फिलहाल नहीं उतारा जाएगा।

प्रधानमंत्री ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बढ़ाया जो इस बार अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षण कठिन हो सकते हैं, लेकिन यह यात्रा का केवल एक पड़ाव है और आप अनेक अवसर उपलब्ध हैं।

ईरान ने बहरीन, कतर व यूएई पर हमले तेज किए

तेहरान/तेल अवीव, 06 मार्च। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष ने पश्चिम एशिया के अधिकांश इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। ईरान खाड़ी के देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उससे संबंधित इलाकों को लगातार निशाना बना रहा है। गुरुवार देर रात बहरीन की राजधानी मनामा में फाईनैशियल हाबर् टावर्स को निशाना बनाया गया। वहीं बहरीन, कतर, सऊदी अरब और जॉर्डन

■ **अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के बाद ईरान ने बदले की कार्यवाही में कई पड़ोसी देशों को निशाना बनाया**

में एयर डिफेंस सिस्टम लगातार उसके हमलों को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। मौजूदा हालात के मद्देनजर कई देशों ने सुरक्षा अलर्ट जारी कर लोगों से घरों में रहने की अपील की है।

सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि सेंट्रल अल-खाज गवर्नरट के पूर्व में एक कूज मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया। बाद में मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि रियाद क्षेत्र के पूर्व में तीन ड्रोन को भी मार गिराया गया।

उधर कतर के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसकी एयर डिफेंस फोर्स ने दोहा स्थित अल उदीद एयर बेस को निशाना बनाकर किए गए एक ड्रोन हमले को विफल कर दिया। यह एयर बेस अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना माना जाता है। दोहा में सुबह करीब 4 बजे धमाकों की जोरदार आवाजें सुनीं गयीं, जो ईरान से आए ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के दौरान हुई थीं। पिछले पांच दिनों में सैन्य बेस को निशाना बनाकर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं।

‘अमेरिका ने दया की, भारत को रूस से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साद अल काबी ने यह भी कहा कि अगर संघर्ष तुरंत समाप्त हो भी जाता है तो कतर को अपनी सामान्य आपूर्ति व्यवस्था को बहाल करने में "हफ्तों से महीनों" तक का समय लगेगा।

भारत में सभी तेल रिफाइनरियों से कहा गया है कि वे "यह सुनिश्चित करें कि उनके पास उपलब्ध प्रोपेन और ब्यूटेन का उपयोग रसोई गैस उत्पादन के लिए किया जाए।" सामान्यतः भारत की अधिकांश एलपीजी मध्य पूर्व से ही आती है, जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है।

भारत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिफाइनरियों को पहले से समुद्र में मौजूद रूसी मूल खरीदने के लिए एक शॉर्ट-टर्म छूट दे रहा है। टैजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा, "वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए, टैजरी विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए अस्थायी तौर पर 30 दिन की छूट दे रहा है।"

"उन्होंने कहा जानवृक्षकर यह शॉर्ट-टर्म छूट दी गई है क्योंकि इससे रूस को कोले लाभ नहीं होगा। क्योंकि यह केवल समुद्र में पहले से फंसे हुए तेल की खरीद फरोख्त की अनुमति देता है। बेसेंट ने इस छूट को एक अस्थायी उपाय के रूप में वर्णित किया, जबकि वॉशिंगटन भारत को अधिक अमेरिकी कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने "यह अस्थायी उपाय ईरान द्वारा वैश्विक ऊर्जा को बंधक बनाने के प्रयास के कारण उत्पन्न दबाव को कम करेगा," उन्होंने कहा।

गल्फ क्षेत्र में यूएस-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के आर्थिक प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। होमजुज जलसंधि मार्ग भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत कच्चे तेल और एलएनजी दोनों के लिए खाड़ी उत्पादकों पर भारी निर्भर है।

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85 प्रतिशत और एलएनजी को जरूरत का 45 से 50 प्रतिशत आयात करता है। भारत के तेल आयात का लगभग 90 प्रतिशत सामान्यतः होमजुज से गुजरता है, जहां टैकर ट्रेफिक अब ठप हो चुका है।

चूंकि भारत द्वारा खरीदी जा रही दिया था। इसके बाद जब समाजवादी नेता होजे लुइस राड्रिगेज ज़ायदो की सरकार सत्ता में आई तो उसने इराक से स्पेनिश सैनिकों को वापस बुला लिया। तब से स्पेन की सरकारों, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की ही, मध्य-पूर्व में अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य अभियानों में शामिल होने को लेकर बेहद सावधान रहती हैं।

यह ऐतिहासिक अनुभव प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज की मौजूदा नीति में भी साफ दिखाई देता है। उनकी सरकार बार-बार कह चुकी है कि इराक जैसी गलतियों को दोहराया नहीं जाना चाहिए। स्पेन के अधिकारियों का कहना है कि मध्य-पूर्व में एकरतारा सैन्य कार्रवाई से अक्सर शांति के बजाय अस्थिरता पैदा हुई है, जबकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को कूटनीति और तनाव कम करने पर ध्यान देना चाहिए। मैड्रिड और वॉशिंगटन के बीच टकराव में आइडियोलॉजी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांचेज एक सेंट्रल-लेफ्ट सोशलिस्ट सरकार का नेतृत्व करते हैं, जो बहुपक्षीय सहयोग, अंतरराष्ट्रीय कानून और कूटनीति पर जोर देती है। इसके विपरीत ट्रंप की विदेश नीति अधिक आक्रामक और एकरतारा रही है। इसलिए ईरान को लेकर यह टकराव कवल रणनीति का मतभेद नहीं, बल्कि दोनों सरकारों की सोच में व्यापक अंतर को भी दिखाता है। तनाव का एक और अंदरूनी कारण नाटो के भीतर रक्षा खर्च को लेकर चल रहा पुराना विवाद है। ट्रंप बार-बार

सुखोई-30 फाइटर जैट क्रैश, दोनों पायलट की मौत

वायु सेना की टीम को हादसा स्थल तक पहुंचने में चार घंटे का समय लगा

काबीं आंगलॉग (असम), 06 मार्च। असम के काबीं आंगलॉग जिले के पहाड़ी इलाके में गुरुवार देर शाम को सुखोई-30 एमकेआई फाइटर एयरक्राफ्ट के क्रैश होने से दोनों पायलटों की मौत हो गई।

दोनों की पहचान स्ववाइज लीडर अनुज और को-पायलट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुरागकर के रूप में हुई है। लेफ्टिनेंट पूर्वेश भारतीय वायु सेना में फ्लाईंग नेविगटर थे। हादसे की आधिकारिक जानकारी आईएफएफ ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए दी है। दुर्घटना स्थल से दोनों वायु सैन्य कर्मियों के शव मिल गए हैं।

भारतीय वायु सेना (आईएफएफ) की एक्स पोस्ट में भारतीय वायु सेना ने

■ **जोरहट से टेकऑफ करने के कुछ देर बाद ही प्लेन काबीं आंगलॉग जिले के दुर्गम पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गया।**

स्ववाइज लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुरागकर के निधन की जानकारी दी गई है। कहा गया है कि दोनों को सुखोई-30 दुर्घटना में घातक चोट आई।

हादसा गुरुवार रात लगभग 7 बजे के आसपास हुआ। विमान से नुक़े टूटने के बाद जोरहाट वायुसेना की टीम ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर खानबीन

शुरू की। हादसास्थल पर वायु सेना की टीम को पहुंचने में लगभग चार घंटे का समय लगा। हालांकि, हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है।

बताया गया है कि जोरहाट से टेकऑफ करने के कुछ ही देर बाद प्लेन काबीं आंगलॉग जिले के दुर्गम पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

सूत्रों ने बताया कि एयरक्राफ्ट सुखोई-30 एमकेआई फाइटर जेट था, जिसने शाम को जोरहाट से उड़ान भरी थी। क्रैश साइट इनसानी आबादी से दूर एक जंगली और पहाड़ी इलाके में है, जिससे वहां के लोगों के लिए तुरंत पहुंचना मुश्किल था।

राजनाथ सिंह व राहुल गांधी ने लड़ाकू विमान हादसे के पायलटों को श्रद्धांजलि दी

■ **रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों पायलटों को उनकी हिम्मत और सेवा के लिए हमेशा आभार व गर्व के साथ याद किया जायेगा।**

नई दिल्ली, 06 मार्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने असम के काबीं आंगलॉग जिले में हुए लड़ाकू विमान हादसे में वायु सेना के पायलटों की शहादत पर दुःख व्यक्त किया।

राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सुखोई-30 विमान हादसे में दोनों पायलटों स्ववाइज लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुरागकर की निधन की खबर सुनकर बहुत दुःख हुआ। देश के लिए उनकी हिम्मत और सेवा को हमेशा गर्व और आभार के साथ याद

फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश का विमान दुर्घटना में शहीद होने का समाचार अत्यंत दुःख और पीड़ादायक है। इन वीर सपुतों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने कहा कि असम में हुई विमान दुर्घटना में दोनों वीर जवानों की शहादत का समाचार अत्यंत दुःख है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक-संतप परिवारों को इस कठिन समय में संवल प्रदान करने की कामना की।

राहुल गांधी ने अपनी शोक संवेदना में कहा कि भारतीय वायुसेना के वीर जवान स्ववाइज लीडर अनुज और

‘अमेरिका ने दया की, भारत को रूस से ...

कच्चे तेल की शिपमेंट पहले से ही बाजार में मौजूद हैं, दिल्ली की मौजूदा कीमतों पर भुगतान करना होगा, बजाय इससे कि वह रूस से पहले की तरह रियायती दरों पर सौदा कर सके।

यह भारत के लिए बुरी खबर है क्योंकि तेल अब 2022 के बाद अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक वृद्धि की ओर बढ़ रहा है, व्यापारियों के अनुसार गोल्डमैन साक्स ने चेतावनी दी है कि कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जा सकती हैं, जबकि जेपी मॉर्गन ने कहा है कि कीमत 120 तक पहुंच सकती है।

भारत पहले ही रूसी कच्चे तेल के दो शिपमेंट्स को खरीद चुका है, जो पास के समुद्र में चल रहे थे।

प्रत्येक टैकर में लगभग 700,000 बैरल तेल है। एक तीसरा रूसी टैकर भी अपना रास्ता बदल चुका है और माना जाता है कि वह भारतीय बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है।

रॉयटर्स के अनुसार, कुल मिलाकर, लगभग 9.5 मिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल वर्तमान में भारत के पास स्थित जहाजों पर है।

वैश्विक स्तर पर, समुद्र में फंसे हुए रूसी तेल की मात्रा कहीं अधिक है। व्यापार खुफिया कर्मी केनगरि के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 130 मिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल टैकरों पर मौजूद है।

चीनी खरीदारों से प्रतिस्पर्धा, जो उसी तेल के लिए बोली लगा रहे हैं, भारत के लिए एक और चुनौती प्रस्तुत करता है।

इस बीच, फेरलू ईथन आपूर्ति की सुरक्षा के लिए, भारत ने तेल रिफाइनरियों से एलपीजी का उत्पादन अधिकृत करने और इसे तीन राज्य-स्वामित्व वाली इंधन खुदरा कंपनियों: इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम को आपूर्ति करने का आदेश दिया है।

अधिकारियों ने यह भी रिफाइनरियों से प्रोपेन और ब्यूटेन को पेट्रोकेमिकल उत्पादन में भेजने से रोकने के लिए कहा है, जिससे उन्हें औद्योगिक उत्पादन के मुकाबले एलपीजी को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर किया गया है। तीन कंपनियों को केवल फेरलू ग्राहकों को ईंधन बेचने का निर्देश दिया गया है।

राज्य-स्वामित्व वाली कंपनियों, जिनमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और मंगलेस्वर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स शामिल हैं, भी व्यापारियों के साथ रूसी माल की त्वरित डिलीवरी प्राप्त करने के लिए बातचीत कर रही हैं। भारतीय राज्य रिफाइनरियों ने अब तक व्यापारियों से लगभग 20 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा है।